advisory bodies have been set up at different levels:—

(i) Kerala—Statutory advisory bodies at taluk level. Though village level advisory bodies are provided for in the law, they have not been set up yet.

(ii) Karnataka—Statutory tribunals consisting of officials and non-officials have been constituted at taluk levels and have started functioning.

(iii) Orissa—A statutory land commission consisting of officials and non-officials has been set up at the State level. District executive committees consisting of both officials and non-official members have been set up. Non-statutory advisory committees at the Tehsil level too have started functioning. Such a committee consists of two officials and two non-officials, one of whom is a member either of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes while the other is a dedicated land reform worker.

(iv) West Bengal Land reforms advisory committee consisting of both official and non-official members are functioning at the block level These committees are non-statutory

(v) U.P.—A State level committee consisting of official and non-official members has been set up and similar bodies will be set up in the districts on the recommendation of the State Committee. This Committee is non-statutory.

(vi) Bihar- A statutory land commission with the Revenue Minister as chairman and some legislators as members has been set up as an advisory body at the State level. It is concerned with the formulation of land policy.

(vii) Haryana—A non-satutory advisory committee consisting of one M.P., four M.L.As. and one ex-M.L.A. and three official members under the chairmanship of the Revenue Minister has been constituted at the State level.

No statutory or non-statutory advisory committee has been set up in the States of Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Gujarat, Rajasthan and Punjab.

(b) and (c) Implementation of the land ceiling laws in the States referred to in reply to part (a) of the question is shown in the statement laid on the Table of the House. [Placed in library. *See* No. LT-9537/75]. The Government of India has asked the State Governments to implement the revised ceiling laws with a time bound programme.

मध्य प्रदेश में धान की नई किस्म

7698. **श्री धनशाह प्रधान :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में चावल की शीघ्र उपज प्राप्त करने के लिये धान (बीज) की नई किस्म तैयार करने के लिये कोई अनुसंधान किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस बारे में अनुसंधान करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान). (क) जी हां।

(ख) विशेष रूप से मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों की वातावरणी स्थितियों के लिए उपयुक्त चावल की नई किस्में विकसित करने पर जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, चावल अनुसंधान संस्थान कटक और अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार प्रायोजना, हैदराबाद के अंतर्गत अनुसंधान जारी है ; जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में चावल के जल्दी तैयार होने वाले

आई आर 15-35-2, जे आर 15-55-2-8, जे आर 15-1-1 और जे आर 16-105-3-1 नामक कल्चर चुने गये हैं। इन किस्मों के तैयार होने की अवधि 85 से 110 दिन है तथा इनकी उपज-क्षमता प्रति हैक्टर 3450 किलो से 7378 किलो० है। ये किस्में अंतिम परख के स्तर पर हैं तथा मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के लिए इनको शीघ्र ही रिलीज करने पर विचार किये जाने की संभावना है।

इसी तरह बाला, पूसा 2-21 और कावेरी नामक किस्में भी मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में अगेती पैदावार के लिए उपयुक्त पायी गयी हैं। कटक के केन्द्रीय धान अनुसंधान संस्थान में सी० आर० 125, 131, 132, 133, 141, 142 और 143 के अतिरिक्त अनेक कल्चर विकसित किये गये हैं, जो इन परिस्थितियों के अन्तर्गत परीक्षण के लिए तैयार हैं। अखिल भारतीय समन्वित धान सुधार प्रायोजना के अन्तर्गत जे० आर० 729-14 और आई० ई० टी० 1444 नामक दो अन्य किस्में भी दण्डकारण्य क्षेत्र के बागानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त पायी गयी हैं। ये दोनों कल्चर जल्द पकने वाले हैं और सीधे बीज डालकर उगाये जा सकते हैं। अखिल भारतीय परीक्षणों से इन दोनों किस्मों की खेती में अच्छी पैदावार की सम्भावना प्रकट हुई है और आगे मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर परीक्षण के लिए उपयुक्त समझी जाती हैं। समन्वित प्रायोजना के अन्तर्गत इनके परीक्षण की योजना तैयार की जा रही है।

(ग) एक धान अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करके उपर्युक्त कार्यक्रम को शक्तिशाली बनाने का प्रस्ताव है। इस केन्द्र में कोरापुट आदिवासी क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं को हल किया जाएगा। अखिल भारतीय समन्वित धान सुधार प्रायोजना की पांचवी पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र की स्थितियों के अनुरूप विशिष्ट अनुसंधान पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है।

Scheme for Welfare of Women and Children

7699. SARDAR SWARAN SINGH SOKHI: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) the names of the schemes sanctioned for the welfare of women and children in the year 1975 for Bihar State;

(b) the names of the schemes proposed and waiting sanction of the Central Government in Bihar and other States in the country; and

(c) the amount sanctioned for such schemes for Bihar, by the Central Government?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI ARVIND NETHAM): (a) to (c) The Ministry of Education and Social Welfare have sanctioned the following schemes for the welfare of women and children during the year 1974-75 for Bihar under the Central and Centrally Sponsored Sectors:—

(i) A sum of Rs. 45,000 was released for one scheme for construction of hostel for working women.

(ii) A sum of Rs. 61,943 was sanctioned for three schemes for the welfare of destitute children.

(iii) A sum of Rs. 58.57 lakhs was sanctioned for supplementary nutrition for pre-school children and pregnant and nursing mothers.

(iv) A sum of Rs. 4,000 was released for one scheme of Organisational assistance to major voluntary social welfare organisations.